mal Power Corporation's Ramagundam Super Thermal Power Project in Andhra Pradesh.

(b) The installed capacity of three units is 200 MW each and that of the fourth unit is 500 MW. The average Plant Load Factor of the units under commercial operation was 77.2 per cent during the year 1987-88.

Contract with Danish firm

1958. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any contract between the Telecommunication Department and a Danish firm has recently been signed; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) M/s. ITI Ltd., jointly with M/s. HCL has signed an agreement with M/s. NKT, Denmark for transfer of technology on manufacture of Fibre Optic Thermal equipment and manufacture of Fibre Cables, respectively. The Agreement was signed on 6th May, 1987. The capacity to be set up by M/s. ITI Ltd., is 610 terminals involving capital investment of Rs. 406.41 lakhs which is inclusive of capital goods, documentation, know-how and technical assistance.

Aid for Anapara Thermal Power Project

1959. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have approved the financial aid from Japan for Anapara Thermal Power Project;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, what are the reasons for the delay; and

(d) by when a decision in this regard is likely to be taken by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) and (b) The Government of Japan have agreed to provide 100 billion Yen through the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) and 40 billion Yen through the Exim Bank of Japan for the Anapara 'B' thermal power project (2x500 MW) of the UP State Electricity Board. The project has been approved for implementation with Japanese assistance.

(c) and (d) Do not arise.

Theft of Electricity

1960. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what is the number of cases of theft of electricity detected by DESU during the last two months;

(b) the steps taken by Government to check the theft of electricity; and

(c) the amount of loss suffered by DESU as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

1961. **श्री अजीत जोगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के 71352 ग्रामों के लिए केवल 9405 डाकघर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पिछड़े तथा आदि-

वासी क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अद्यतन आंकड़े निम्नानुसार है :—

(i) मध्य प्रदेश में ग्रामों की संख्या 71,352

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 9,521

(ख) जी हां।

(ग) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 230 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए 148 डाकघर भी शामिल हैं।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक का रिक्त पद

1962. **श्री अजीत जोगी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, प्रबंध निदेशक का पद लम्बे अरसे से रिक्त है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि ऐसे महत्वपूर्ण पद के न भरे जाने का कम्पनी की दक्षता तथा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यह पद कब तक भर दिया जायेगा?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां। यह पद 15-7-1988 से रिक्त है।

(ख) यह पद समय पर इसलिये नहीं भरा जा सका क्योंकि उक्त पद पर नियुक्ति के लिये बनाया गया पैनल (सूची) में दूसरे स्थान के व्यक्ति के विरुद्ध एक आपराधिक मामला लंबित था। संबद्ध अधिकारी ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपना फैसला समय पर नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला 2-9-1988 को दिया जिसमें संबंधित अधिकारी को सभी आरोपों से दोष-मुक्त कर दिया। इस बीच, उक्त पैनल (सूची), जो 27-8-1988 तक ही मान्य था, की विधि समाप्त हो गयी। इसलिये उक्त पैनल (सूची) को पुनर्मान्य कराने के लिये पी० ई० एस० बी० से संपर्क किया जाना आवश्यक हो गया जो कि अब 31-12-1988 तक के लिये पुनर्मान्य हो गया है।

(ग) शीर्षस्थ रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने से संगठन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस मामले में विभाग के उपयुक्त वर्णित अपरिहार्य कारणों के कारण रिक्त पद को भरना संभव नहीं हो पाया। इस संबंध में रिक्त पद को शीघ्र भरने के लिये कदम उठाये गये हैं।

मध्य प्रदेश के पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों में टेलीफोन सुविधाएं

1963. **श्री अजीत जोगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों के नाम क्या है, जिनमें चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन सुविधा दे दिये जाने की संभावना है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति की गई है ; और